

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2016/ भाद्र 7, 1938

No. 337]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 17, 1938

(भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 अगस्त, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल. ए. डी.-एन.आर.ओ./ जी. एन./ 2016-17/010.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23 अक तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 झक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम,
 2014 में, -

4200 GI/2016 (1)

- (I) विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
 - "परंतु यह और कि इस खंड के अधीन चूकों पर विचार, इन विनियमों के अनुसार और साथ ही अनुसूची-II में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के अनुसार, किया जाएगा।"
- (II) अनुसूची-II में, अध्याय I में, -
 - (1) मद 11, मद 12 के रूप में पुन:संख्यांकित हो जाएगी;
 - (2) मद 10 के पश्चात् और इस प्रकार पुन:संख्यांकित मद 12 से पूर्व, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् -
 - "11. एतद्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि -
 - (क) विनियम 5 के खंड (2) के उप-खंड (ख) का प्रयोजन सभी प्रकार के कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में निपटारों को प्रतिषिद्ध करना नहीं है।
 - (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) का खंड (ख) केवल उन चूकों (डिफॉल्ट्स) को अयोग्य ठहराता है, जो 'गंभीर' हों और-
 - (i) जिनका बाजार पर व्यापक प्रभाव हो, या
 - (ii) जिनसे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश (विनिधान) करने वाले निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को बहुत अधिक हानियाँ होती हों, या
 - (iii) जिनसे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश (विनिधान) करने वाले निवेशकों (विनिधानकर्ताओं), खासकर छोटे निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) और छोटे शेयरधारकों, के अधिकार प्रभावित होते हों।
 - (ग) इस प्रकार, खंड (ख) के अनुसार अयोग्य ठहराए जाने के लिए, यह अनिवार्य है कि चूक गंभीर हो, और वह उपरोक्त क्रम सं. (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित किसी श्रेणी या सभी श्रेणियों के अंतर्गत आए। इसके होते हुए भी, जहाँ ये दोनों ही मानदंड पूरे होते हों, वहाँ निपटारे हेतु आवेदन पर विचार किया जा सकेगा, यदि खंड (ख) के पहले परंतुक के अनुसार आवेदक ने निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को हुई हानियों की पूर्ति कर दी हो या आवेदक निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को हुई हानियों की पूर्ति करने का इरादा रखता हो, बशर्ते कि वह लिखित रूप में यह वचन प्रस्तुत करे कि,-
 - 'मैं / हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समक्ष, केवल प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे के सीमित प्रयोजन हेतु, आरोप स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं।'
 - (घ) इसकी 'गंभीरता' पर विचार करते समय, चूक (डिफॉल्ट) को इस संदर्भ में देखा जाएगा कि चूक का स्वरूप क्या था और आवेदक द्वारा क्या भूमिका निभाई गई। यह जरूरी नहीं है कि, यथास्थिति, कारण बताओ सूचना (शो

कॉज़ नोटिस) या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) रिपोर्ट या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (डेसिग्नेटिड अथॉरिटी) की रिपोर्ट में आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर ही इस संबंध में निर्णय लिया जाए। इस संबंध में, आवेदक के खिलाफ साक्ष्य की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता और लगाए गए आरोप के आधार पर भी विचार किया जा सकेगा या इस बात पर भी विचार किया जा सकेगा कि अन्वेषण / जाँच / निरीक्षण, आदि (यदि कोई हो) के दौरान आवेदक ने कितना सहयोग दिया।

- (ङ) इसके अलावा, यह तथ्य चूक की 'गंभीरता' पर विचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण कारक होगा कि मामला केंद्रीय सरकार द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) को भिजवाया गया अथवा कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहार (व्यवहारों) से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी बैंकिंग या सूक्ष्म वित्त संस्था या प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) या निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के कार्यों को प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) होता हो।
- (च) बाजार पर व्यापक प्रभाव : से वे चूकें अभिप्रेत होंगी जिनका प्रभाव पूरे प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) पर पड़ता हो, न कि महज उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) तथा उसके निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) पर, जिसके संबंध में अन्वेषण / जाँच / निरीक्षण, आदि किया जा रहा हो।
- (छ) निवेशकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली चूकों : का संदर्भ निवेशकों के अधिकारों पर पड़ने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रभाव से होगा, जिसमें सम्मिलित है प्राप्त शिकायतों की संख्या, खासकर छोटे निवेशकों और छोटे शेयरधारकों से प्राप्त । गुणात्मक प्रभाव का संदर्भ निवेशकों के अधिकारों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव से है, जैसे कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों के परिणामस्वरूप स्क्रिप की रेटिंग में कमी या न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) संबंधी मानदंडों के संबंध में चूक करते हुए संबद्ध पक्षकारों (रिलेटिड पार्टीज़) को कपटपूर्ण ढंग से निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) करके संप्रवर्तक धारिताओं (प्रोमोटर होल्डिंग्स) में बढ़ोतरी, आदि । परिमाणात्मक प्रभाव का संदर्भ निवेशकों को हुई उन हानियों से है, जिनकी गणना की जा सके (और जितनी की जा सके)।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014,
 सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/37/50 द्वारा, 9 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में
 प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 तत्पश्चात् :-
 - (1) 15 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2014-15/08/1491, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 26th August, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/010.—In exercise of the powers conferred under section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, namely,—

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2016.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014,-
 - (I) In regulation 5, in sub-regulation (2), in clause (b) after the proviso the following shall be inserted, namely-
 - "Provided further that the defaults under this clause shall be considered in accordance with these regulations and also the guidelines specified in Schedule-II."
 - (II) In Schedule- II, in Chapter I, -
 - (1) item (11) shall be renumbered as item (12);
 - (2) after item (10) and before item (12) so renumbered, the following item shall be inserted, namely-
 - "(11) It is hereby clarified that –
 - (a) the purpose of sub-clause (b) of clause (2) of regulation 5 is not to prohibit the settlements in respect of all kinds of fraudulent and unfair trade practices.
 - (b) clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 5 disqualifies only the defaults which are 'serious' and-
 - (i) have market wide impact, or

- (ii) cause substantial losses to investors in securities, or
- (iii) affect the rights of investors in securities, especially retail investors and small shareholders.
- (c) Thus, in order to fall in disqualification of clause (b), the default must be serious and it must fall in any or all of the categories mentioned in points (i), (ii) and (iii) above. Notwithstanding the same, where both these criteria are attracted, the application may be considered for settlement, if the applicant has made or intends to make good the losses to the investors in terms of the first proviso to clause (b), provided he undertakes in writing that,-
 - 'for the limited purpose of settling the administrative and civil proceedings I/We admit the charge before the Securities and Exchange Board of India.'
- (d) While considering its 'seriousness', the default shall be seen in the context of its specific nature and the role played by the applicant. The charges against the applicant in the show cause notice or the investigation report or the report of the designated authority, as the case may be, may not be the only deciding factor in this regard. The weight and sufficiency of the evidence and the basis of the charge levelled against the applicant or the extent of his co-operation during the investigation/inquiry/inspection, etc., if any may also be taken into account.
- (e) Further, the fact that the case has been referred to the Serious Frauds Investigation Office by the Central Government or the fraudulent and unfair trade practices, directly or indirectly, pose a systemic risk to the functions of any banking or micro-finance institution or a systemically important non-banking financial company or stock exchange or clearing corporation or a depository shall be relevant factors for considering the 'seriousness' of the default.
- (f) Market wide impact: shall mean the defaults which have a bearing on the securities market as a whole and not just the listed security and its investors which is under investigation/inquiry/inspection, etc.
- (g) The defaults which affect the right of investors: shall refer to the qualitative and quantitative impact on the rights of investors, including the number of complaints received, especially from retail investors and small shareholders. A qualitative impact refers to an indirect impact on the rights of investors, such as reduction in rating of a scrip as a result of the fraudulent and unfair trade practices or an increase in promoter holdings through a fraudulent private placement to related parties in default of minimum public shareholding norms, etc. A quantitative impact refers to the quantifiable losses to investors, to the extent determinable."

U. K. SINHA, Chairman [ADVT III/4/Exty./222]

Footnote:

- 1. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on January 09, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/37/50.
- 2. The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were subsequently amended on:-
 - (1) 15th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/08/1491.